भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 833
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन का समापन

†833. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने प्रारंभ में जल जीवन मिशन (जेजेएम) को दिसंबर, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त मिशन को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 2.79 लाख करोड़ रुपए की मांग की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) क्या व्यय सचिव के नेतृत्व वाले पैनल ने अनुरोध की गई राशि के केवल एक हिस्से को ही मंजूरी दी है और दिसंबर 2028 तक केंद्रीय वित्त पोषण सहायता में 46 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव रखा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा वित्त पोषण की इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसकी विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन की गति और गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार ने अगस्त 2019 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है। शुभारंभ के समय, सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को भी मंजूरी दी गई। स्वीकृत किए गए केंद्रीय परिव्यय का लगभग पूरा उपयोग किया जा चुका है।

मिशन के शुभारंभ के समय, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 21.07.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.44 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 21.07.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.94%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तदनुसार, जल जीवन मिशन को बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ 2028 तक जारी रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*****